State	(Area in 000 Hectare) Lane Area Covered under DPAP
4. Haryana	301
5. Jammu & Kashmir	857
6. Karnataka	8505
7. Madhya Pradesh	4078
8. Maharashtra	11648
9. Orissa	2210
10. Rajasthan	3005
11. Tamil Nadu	1778
12. Uttar Pradesh	4923
13. West Bengal	1120
Total	53664

भूक्षरण के नियंत्रण के लिए उठाये गये कदम

4830. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या प्रधान मंत्री 23 मार्च, 1995 को राज्यसभा में पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 1640 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा भूक्षरण को रोकने के लिए क्या-क्या कदम उठाये गये हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (बंजर भूमि विकास विभाग) (कर्नल राम सिंह): भूमि और जल के अवैज्ञानिक ढंग से प्रबन्ध के परिणाम स्वरूप जल और वायु के क्रियाशील होने की वजह से भूमि का कटाव होता है। मध्य प्रदेश सहित देश में भूमि कटाव को न्यूनतम करने के उद्देश्य से वाटरशैड आधार पर केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं की मार्फत विभिन्न योजनायें शुरू की जा रही हैं। इन योजनाओं में भूमि-आधारित विभिन्न गतिविधियां जिनमें बांध लगाना, खाई खोदना, गली प्लागिंग, भू-संरक्षण ढांचे आदि शामिल हैं। इन योजनाओं का नैतिक लक्ष्य अलग-अलग वर्ष में अलग-अलग होता है तथा यह केन्द्र और राज्य सरकारों के योजना आवंटन के आधार पर तय किया जाता है।

ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय ने हाल ही में भूमि की विभिन्न श्रेणियों जिनमें बंजर भूमि भी शामिल है, के वाटरशेड विकास हेतु अपनी क्षेत्र विकास योजनाओं जिनमें सुखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम/समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना जहां पर भूमि के कटाव वाली गतिविधियों सहित भूमि विकास गतिविधियां शुरू की जाएंगी, के लिए सामान्य मार्गदर्शिकाएं जारी की हैं।

बंजर भूमि विकास विभाग में समेकित बंजर भूमि विकास परियोजना स्कीम में भूमि के कटाव को रोकने के लिए परियोजना परिव्यय का अधिकतम 20% निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार से अनुदान सहायता योजना, जिसके अन्तर्गत स्वयंसेवी एजेंसियों को वित्तीय सहायता दी जाती है, के तहत भू-संरक्षण के लिए विशिष्ट प्रावधान किया गया है। तथापि, चूंकि, वन रोपण/वृक्षा-रोपण इन दोनों योजनाओं की मुख्य गतिविधियां है, इन गतिविधियों के द्वारा भूमि के कटाव को रोकने का उद्देश्य भी पूरा हो जाता है।

Difference In Wages of Male and Female Unskilled Workers

4831. PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether any study has been carried out to find out if there is any gap in the wages of male and female unskilled workers in some of the States; and

(b) if so, the outcome of the study and the reasons for the gender and regional bias in rural employment schemes?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINSITRY OF RURAL AREAS & EMPLOYMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI UTTAMBHAI H. PATEL): (a) and (b) No, Sir. However, a Concurrent Evaluation study of the Jawahar Rozgar Yojana (JRY) conducted in 1992 *inter-alia*, revealed that there was a disparity in the average wages paid per manday to male and female unskilled workers in certain States like Andhra Pradesh, Kerala, Maharashtra, Tamil Nadu and Pondicherry. In all other States/UTs, the survey did not reveal any sex-wise disparity in the average wages paid. The disparities may be on account of the type and quantum of work done by male and female workers respectively. As regards wage rates, under the guidelines for the Jawahar Rozgar Yojana (JRY) and the

Employment Assurance Scheme (EAS), which are two important rural employment programmes, the implementing agencies are required to adhere to the provisions under Equal Remuneration Act, 1976 in terms of which a duty has been cast on the employer to pay equal remuneration to men and women workers for the same work or for the work of similar nature as well as to not discriminate while recruiting men and women workers.

Augmentation of DPAP In Gujarat

4832. SHRI GOPALSINGH G. SOLANKI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government of Gujarat made a plea to the Centre for augmentaiton of Drought Prone Areas Programme in the State by inclusion of 16 new Talukas of Kachh, Bharuch, Panchmahal, Dang and Mehsana districts in the DPAP;

(b) if so, the details thereof; and

(c) whether Government would expedite its clearance so that work on DPAP in the new Talukas of said districts can be started in the right earnest?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL AREAS & EMPLOYMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI UTTAMBHAI H. PATEL): (a) and (b) In the Memorandum submitted to the Technical Committee on Drought Prone Areas Progrmme (DPAP) and Desert Developmet Programme (DDP) constituted by the central Government, government of Gujarat requested for transfer of Kachh District from DPAP to DDP and inclusion of 44 new Talukas from Amreli, Bhavnagar, Jamnagar, Panchmahal, Rajkot, Kachh, Vadodara, Bharuch and Junagadh Districts. Government of India, following the criteria laid down by the Technical Committee for inclusion of new blocks under DPAP and DDP, has included 32 new Talukas from Bharuch, Vadodara, Panchmahals, Sabarkantha, Amreli Bhavnagar, Dangs, Junagadh and Valsad Districts under DPAP; 15 Talukas from Jamnagar, Rajkot and Kachh Districts under DDP and transferred 23 Talukas from Jamnagar, Rajkot, Kachh, Surendranagar Districts from DPAP to DDP.

(c) New Blocks/Districts have been included under DPAP and DDP with effect from 1st April, 1995 and the State Government has already been asked to launch these Programmes in the new Talukas.

बंजरभूमि के विकास के लिए गुजरात के स्वैच्छिक संगठनों से प्रस्ताव

4833. **श्री गोपाल सिंह जी० सोंलकी: क्या प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गुजरात के स्वैच्छिक संगठनों से वहां बंजरभूमि के विकास हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिलेवार ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान में बंजरभूमि के विकास कार्य में संलग्न स्वैच्छिक संगठनों के जिलेवार नाम क्या हैं और पिछले तीन वर्षों के दौरान इनमें से किन-किन संगठनों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी गयी है; और

(घ) सरकार द्वारा भूक्षरण को रोकने के लिए क्या-क्या कदम उठाये गये हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (परती भूमि विकास विभाग) (कर्नल राम सिंह): (क) जी, हां।

(ख) स्वैच्छिक एजेंसियों से प्राप्त प्रस्तावों का जिलेवार ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है। **(नीचे** देखिए)

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान परती भूमि विकास से जुड़ी वित्तीय सहायता प्राप्त स्वंयसेवी एजेंसियों के जिलावार नाम विवरण-2 में दिए गये हैं।

(घ) भूमि का कटाव आमतौर पर वायु और जल के क्रियाशील होने की वजह से होता है। इस योजना के अन्तर्गत वनरोपण/वृक्षारोपण गतिविधियों के द्वारा भूमि का और अधिक कटाव रूक सकेगा। इसके अलावा योजना में बांध लगाने, खाई खोदने, गली-प्लगिंग आदि जैसे उपायों की मार्फत भूमि के कटाव को रोकने के लिए विशिष्ट घटक की व्यवस्था की गई है।